Implementation of JRY

2041. SHRI GAYA SINGH:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any representation dated 27th March. 1993 regarding prevailing corruption in implementation of Jawahar Rozgar Yojana and distribution of land by the "Pradhan" of village Mirpur, Tehsil Khair in Janpad Aligarh (Uttar Pradesh) and signed by some members of Gram Panchayat have been received:

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any enquiry has been made and action taken thereon; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Applicatons judged with capart

2052. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that over 7500 applications lodged with Council for Advancement of People's Action and Technology are yet to be screened and processed;

(b) whether such applications will be returned to the applicants;

(c) the steps being taken to streamline CAPART; and

(d) whether it is also a fact that CAPART has become top-heavy in terms of management?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) After scrutiny applications which are not as norms laid down by CAPART will be returned to the applicants.

(c) After careful examination suitable steps will be initiated to streamline the functioning of CAPART.

(d) No, Sir.

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत खोदे गए कुएं

2043. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जवहार रोजगार योजना के अंतर्गत खोदे गए कुएं सूख गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन कुओं के सूख जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) दस लाख कुआं की योजना नामक जवाहर रोजगार की एक उप-योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीब छोटे तथा सीमान्त किसानों और मुक्त बंधुआ-मजदूरों को निःशुल्क खुले सिंचाई कुएं उपलब्ध कराना है 10 लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत लाभार्थी स्वयं अपने कुओं का निर्माण करते हैं यदि कोई कुआं कम पानी अथवा खराब पानी अथवा ढांचा सम्बंधी विफलता के कारण असफल हो जाता है तो कुएं की खुदाई के लिए किए गए वास्तविक खर्च के प्रतिशत के बराबर मुआवजा दिया जाता है ।